oriented policies and investment programmes to -raise the rate of growth in GDP with which the level of consumption expenditure is related. Programmes to alleviate poverty by generating employment and enhancing the income of poor have been particularly strengthened. The network of ' the Public Distribution System (PDS) has been expanded over the years in order to increase availability of food to' the poor. Government, in consultation with State Government and U.T. Administrations, have taken steps to revamp the Public Distribution System to improve its reach and to eliminate leakages or malpractices. Preference is now being given to the population living in most difficult areas of the country, such as drought prone areas, desert areas, tribal areas, certain designated hilly areas and urban slum areas. Eighth Plan has given a high priority to population control, literacy and human development.

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड का गठन

132. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस आशय का एक आश्वासन दिया गया था कि पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए शीघ्र ही एक बोर्ड का गठन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सभा में दिनांक 17-8-92 के तारांकित प्रश्न सं. 522 का उत्तर देते समय अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय के लिए अलग से पारिस्थितिकीय विकास प्राधिकरण के गठन का मामला विचाराधीन है ।

(ख) उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में जोत क्षेत्र की चकबन्दी में प्रगति

1323. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में जोत क्षेत्र के लिए की जा रही चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है; और

(ग) क्या गढ़वाल में भी जोत क्षेत्र की चकबंदी का कार्य प्रगति पर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Drought prone area programme in A.P.

1324. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the present extent of Drought Prone Area Programme (DPAP) in Andbra Pradesh ;

(b) whether any assessment has been made of the implementation of DPAP in Andhra Pradesh ; and

(c) what further steps are under consideration to mitigate the effects of regular drought in some areas in Andhra Ptadesh ?

THE MINISTER OF STATE IN TH^ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Presently sixty nine blocks <in the Districts of Anantpur, Chittoor, Cuddapah, Kurnool, Mahabubnagar. Nalgonda, Prakasam and Rangareddy are covered under the Drought Prone Areas Programme in Andhra Pradesh.

(b) The implementation of DPAP in all concerned States including Andhra Pradesh is being reviewed periodically by ;*i* Central Sanctioning Committee to assess the performance of the programme and provide suitable policy directions so as to improve it.

(c) To mitigate the effects of drought, three core sectors, namely Land Resources Development, Water Resources Development and Afforestation and Pasture Development have been identified as the thrust areas for development of DPAP blocks on watershed basis. To speed up the implementation of drought mitigating works, the DPAP allocation to Andhra Pradesh for 1993-94 is being enhanced by about 50% of the existing allocation of Rs. 1203 lakhs.

ग्रामीण विकास के अंतर्गत गुजरात में वित्तीय सहायता दिया जाना

1325. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार, योजना-वार तथा वर्ष-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का मूल्यांकन करने तथा भूलभूत सुविधाओं का पता लगाने के लिए कोई निगरानी अभिकरण स्थापित किया है ताकि राज्यों द्वारा धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है और इसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए बिना इसे जारी रखने का औचित्य क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलावार, कार्यक्रम-वार तथा वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में मिनी मिशन से संबंधित सूचना जिलावार दी गई है जबकि राज्य हेतु वर्ष 1989-90 से लेकर 1992-93 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के बारे में सूचना विवरण-2 में दी गई है **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है। बुनियादी स्तर पर, खण्ड स्तर के कर्मचारियों को कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में शामिल किया जाता है। जिला स्तर पर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषद आवधिक रिपोर्टों की मार्फत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फील्ड के दौरे किए जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय में अन्य लोगों के अलावा, स्थानीय विधायकों और संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शासी निकाय की सामान्यतः तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राज्य स्तर पर कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। राज्य स्तर पर मुख्यालय में कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए परियोजना निर्धारण एवं निगरानी सैल का भी गठन किया गया है। केन्द्र स्तर पर मंत्रालय द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और उसके अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों की मार्फत कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक सतत प्रणाली तैयार की गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने हेतु उपाय करने के लिए कई ख्यातिप्राप्त अनुसंधान संगठनों को शामिल करके मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीन दौर पूरे हो गए हैं